राजू प्रेमजी

बनाम

सीमा शुल्क एनईआर शिलांग इकाई

आपराधिक अपील संख्या 1647, 2007

6 मई 2009

[एस.बी. सिन्हा और आर.एम. लोधा, जे.जे.]

स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985:

एस.एस. 21, 28 और 29 -पुलिस हिरासत में किए गए कबूलनामे के आधार पर दोषसिद्धि - आयोजित: दोषसिद्धि उचित नहीं है क्योंकि अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई करने के लिए पूर्व शर्तों का पालन नहीं किया गया था, कोई तलाशी वारंट या प्राधिकरण प्राप्त नहीं किया गया था - 'व्यक्ति' की तलाश की गई थी धारा 50 की आवश्यकता का अनुपालन किए बिना मामले को कस्टम अधिकारियों को स्थानांतरित करने के लिए पुलिस अधिकारियों की ओर से कोई तर्क नहीं था - उन्हें कोई समन नहीं भेजा गया था - अपीलकर्ता पुलिस की हिरासत में थे और इसलिए पुलिस हिरासत में रहते हुए उनके द्वारा दिया गया कोई भी बयान गलत होगा साक्ष्य अधिनियम की धारा 26 के तहत साक्ष्य में अग्राह्य होना - मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, स्वीकारोक्ति को

अपीलकर्ताओं द्वारा स्वेच्छा से किया गया नहीं कहा जा सकता है - क्योंकि उनके कब्जे से प्रतिबंधित सामग्री नहीं पाई गई, इसलिए सबूत का भार कभी भी उन पर नहीं डाला गया - साक्ष्य अधिनियम, 1872-धारा 26.

अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि पुलिस पार्टी को सूचना मिली कि आरोपी व्यक्तियों के पास नशीली दवाएं हैं। पुलिस दल ने आरोपियों को पकड़ लिया और पुलिस अधीक्षक कार्यालय ले आये। भौतिक खोज पर, कुछ भी नहीं मिला। उनसे पूछताछ की गई, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर खुलासा किया कि ड्रग्स आरोपी नंबर 1 के कब्जे में थे। पुलिस पार्टी ने कस्टम अधिकारियों को सूचना दी. अपीलकर्ताओं को पुलिस अधिकारियों ने हिरासत में ले लिया और सीमा शुल्क अधिकारियों को सौंप दिया। आरोपी व्यक्तियों द्वारा एनडीपीएस अधिनियम की धारा 67 के तहत बयान दिए गए थे। एक औपचारिक एफआईआर अगले दिन दर्ज कराई गयी। सभी आरोपी व्यक्तियों को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया और आगे की पूछताछ के अधीन, दोनों अपीलकर्ताओं ने अपना बयान दिया। इसके बाद उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। आरोपी अपने कबूलनामे से मुकर गए।

ट्रायल कोर्ट ने उन्हें नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 की धारा 21, 28 और 29 के तहत दोषी ठहराया। उच्च न्यायालय ने भी इसकी पुष्टि की। इसलिए अपीलें. अपीलकर्ताओं की ओर से

यह तर्क दिया गया कि कथित बयान अपीलकर्ताओं द्वारा हिरासत में रहते हुए अधिकृत अधिकारियों के समक्ष दिए गए थे और इसलिए वे साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 26 के तहत आते हैं।

न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुए

माना: 1. नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 में कड़ी सजा का प्रावधान है। जहां कोई क़ानून कठोर शक्ति प्रदान करता है और जमानत देने से संबंधित मामले सहित कठोर दंडात्मक प्रावधानों का प्रावधान करता है, वहां पूर्ववर्ती शर्तों का ईमानदारी से पालन किया जाना चाहिए। [पैरा 11] [848-बी-सी]

2. पुलिस अधिकारियों को एक सूचना मिली. पुलिस अधिकारी एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के तहत सशक्त अधिकारी थे। उन्हें इसे लिखित में देना था ताकि उच्च अधिकारियों को इसके बारे में अवगत कराया जा सके। कोई तलाशी वारंट या प्राधिकरण प्राप्त नहीं किया गया था। कुछ सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी तैनात किये गये। एस.आई., पीडब्लू-10 द्वारा छापा मारा गया। अपीलकर्ताओं को हिरासत में लिया गया और पीडब्लू-9 के कार्यालय में लाया गया। फिर भी उनसे कोई बयान देने के लिए नहीं कहा गया. उन्हें बुलाया तक नहीं गया. अधिनियम की धारा 50 के प्रावधानों का अनुपालन किए बिना उनके जी व्यक्तियों की तलाशी ली गई। जाहिर तौर पर उनसे पूछताछ की गई. पूछताछ करने पर ही उन्होंने

आरोपी नंबर 1 के पते के बारे में बताया. उपरोक्त स्थिति में, यह समझना मुश्किल है कि एच सीमा शुल्क अधिकारियों को क्यों सूचित करना पड़ा। पुलिस अधिकारी वे स्वयं तलाशी और जब्ती कर सकते थे। इसके लिए सशक्त होने के कारण उन्हें अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना चाहिए था। यद्यपि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 53 के तहत जारी अधिसूचना के अनुसार सीमा शुल्क अधिकारियों को पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी की शक्तियां प्रदान की जा सकती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पुलिस अधिकारियों को उनके अधिकार क्षेत्र से वंचित कर दिया गया है। [पैरा 11] [848-सी-जी]

3.1. मामले को सीमा शुल्क अधिकारियों को स्थानांतरित करने के लिए पुलिस अधिकारियों के पास कोई तर्क नहीं था। यह स्वीकार किया गया है कि अपीलकर्ताओं को पीडब्लू सहित पुलिस अधिकारियों द्वारा आरोपी नंबर 1 के गांव में ले जाया गया था। पीडब्लू 9 और पीडब्लू10. सीमा शुल्क अधिकारी बहुत बाद में उनके साथ जुड़े। आरोपी नंबर 1 के घर की तलाशी विशेष रूप से सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा नहीं की गई थी। मौजूद सभी पुलिस अधिकारी खोजबीन में जुट गये. जाहिर तौर पर तलाश सूर्यास्त के बाद की गई। जैसा कि पीडब्लू-9 को शाम लगभग 6.30 बजे सूचना प्राप्त हुई; जैसा कि अदालत के समक्ष उसके बयान से स्पष्ट है कि वह रात लगभग 10.00 बजे आरोपी नंबर 1 के घर से निकला था। जबकि सीमा शुल्क अधिकारी अभी भी कुछ अन्य औपचारिकताएँ निभा रहे थे।

चारों आरोपियों को आगे की पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन लाया गया और अगली तारीख पर सीमा शुल्क अधिकारियों ने पुलिस अधिकारियों को सूचित किया कि उन दोनों को गिरफ्तार करना आवश्यक है। उस समय ही उनकी अभिरक्षा सीमा शुल्क अधिकारियों को सौंप दी गई थी। पीडब्लू-7 वह अधिकारी था जिसके सामने कथित बयान दिए गए थे। यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि उन्हें कोई समन भेजा गया था। ऐसा कोई समन रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया. कोई सौदा हुआ हुआ नहीं पाया गया। अभियुक्तगण एवं सूचक आपस में ही बात कर रहे थे। वह उनकी बातचीत भी नहीं सुन सका। माना जाता है कि सूचना देने वाले से पूछताछ नहीं की गई जिसके लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। माना कि प्रत्येक आरोपी से तीन बयान लिए गए। पहला एक कथात्मक था। दूसरा सवाल-जवाब के रूप में था. तीसरा कथन था औपचारिक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के बाद स्वीकारोक्तिपूर्वक लिया गया। [पैरा 12, 13, 14, 15] [848-एच; 849-ए-जी]

3.2. यह स्वीकार किया गया है कि संबंधित अधिकारी, पीडब्लू-7, ने सोचा था कि अभियुक्तों से बिना संख्या के कई बार पूछताछ की जा सकती है जब तक कि वे अपनी संतुष्टि के अनुरूप उत्तर नहीं देते। इसलिए, एक सशक्त अधिकारी अधिनियम के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के संबंध में किसी भी जांच के दौरान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित किसी भी व्यक्ति से पूछताछ करने का हकदार है। चूंकि 'पूछताछ' शब्द को

एनडीपीएस अधिनियम के तहत परिभाषित नहीं किया गया है, इसका अर्थ आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 2 (जी) के साथ-साथ व्युत्पत्ति संबंधी अर्थ में भी दिया गया है और इसे लागू करने के तरीके के रूप में माना जा सकता है। [पैरा 16,18] [849-जी; 850-डी-एफ]

4.1. प्रारंभ से ही यह स्वीकार किया गया कि अपीलकर्ता पुलिस हिरासत में थे। उनसे पुलिस अधिकारियों ने पूछताछ की। वे स्वतंत्र व्यक्ति नहीं थे. वे संयम के आदेशों के अधीन थे और इस प्रकार पुलिस अधिकारियों की हिरासत में होंगे। किसी पुलिस अधिकारी की हिरासत में रहते हुए उनके द्वारा दिया गया कोई भी बयान साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 26 के संदर्भ में साक्ष्य में अस्वीकार्य होगा।[पैरा 19] [850-एफ-जी]

4.2. केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार सीमा शुल्क अधिकारी एफ पुलिस स्टेशन का एक प्रभारी अधिकारी था। इसलिए, एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को उपलब्ध सभी शक्तियाँ उसके पास उपलब्ध थीं। एक प्रभारी अधिकारी की शक्ति का एक गुण संज्ञेय अपराध के आयोग की जांच करने की शक्ति है। वह आरोप पत्र भी दाखिल कर सकते हैं. [पैरा 20] [851-सी-डी]

पंजाब राज्य बनाम बलदेव सिंह (1999) 6 एससीसी 172; कन्हैयालाल बनाम भारत संघ (2008) 4 एससीसी 668 -संदर्भित।

5. इकबालिया बयान स्वैच्छिक है और किसी दबाव से मुक्त है, इसका निर्णय प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से किया जाना चाहिए। किसी भी घटना में अगर वे अंदर थे पुलिस अधिकारियों और सीमा शुल्क अधिकारियों की हिरासत, हालांकि वे शब्द के सख्त अर्थ में आरोपी नहीं थे, उनके द्वारा किया गया कोई भी बयान साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 26 के संदर्भ में स्वीकार्य नहीं होगा। आरोपी द्वारा बयान वापस ले लिया गया था कुछ दिन बाद ही नंबर 4. विशेष न्यायाधीश ने इस तरह के मुकरने के तथ्य पर विचार किया है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यह नहीं कहा जा सकता कि स्वीकारोक्ति अपीलकर्ताओं द्वारा स्वेच्छा से की गई है। चूंकि अपीलकर्ताओं के पास प्रतिबंधित पदार्थ नहीं पाया गया, इसलिए सबूत का बोझ उन पर कभी नहीं पड़ा। [पैरा 23, 24, 26] [852-एच; 853-ए, ई; 854-बी-सी]

मोहतेशाम मो. इस्माइल वि. विशेष. निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय (2007) 8 एससीसी 254; नूर आग़ा वि. पंजाब राज्य और अन्य 2008 (9) स्केल 681; कोचन वेलायुधन बनाम. केरल राज्य एआईआर 1961 केरल 8 -संदर्भित।

केस कानून संदर्भ

(1999) 6 एससीसी 172 संदर्भित पैरा 21

(2008) 4 एससीसी 668 संदर्भित पैरा 22

(2007) 8 एससीसी 254 संदर्भित पैरा 23

2008 (9) स्केल 681 उल्लेख किया गया है करने के लिए भेजा 23 के लिए

एआईआर 1961 केरल 8 करने के लिए भेजा 25 के लिए

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 1647/ 2007

की आपराधिक अपील संख्या 4 (एसएच)/2006 में माननीय गौहाटी उच्च न्यायालय, शिलांग पीठ के निर्णय और आदेश दिनांक 06.09.2007 से साथ

आपराधिक अपील संख्या 956/2009

यू. यू. ललित, देबजानी दास पुरकायस्थ, अनु गुप्ता, विकास

उनके साथ ए महाजन, विनोद शर्मा, भास्कर वाई कुलकर्णी

अपीलकर्ता श्रबानी चक्रवर्ती, आशा जी. नायर, अनिल कटियार (बी.वी. के लिए)

बलराम दास), प्रतिवादी की ओर से। बी न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

एस.बी. सिन्हा, जे.

अनुमोदन स्वीकृत

1. इन दो अपीलों में तथ्य व कानून के सामान्य प्रश्न शामिल हैं दिनांक 6 सितंबर 2007 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध निर्देशित हैं। सितंबर, 2007 को गौहाटी की एक खंडपीठ द्वारा पारित किया गया 2006 की आपराधिक अपील संख्या 3 (एसएच) और 2006 की 4)एसएच) में उच्च न्यायालय ने आपराधिक (एनडीपीएस) मामले में विद्वान विशेष न्यायाधीश, एनडीपीएस, डी शिलांग द्वारा 21 जून, 2006 को पारित दोषसिद्धि और सजा के फैसले की पुष्टि की। .26/2003 जिसके तहत दोनों अपीलकर्ताओं को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (संक्षेप में 'एनडीपीएस एक्ट') की धारा 29 के तहत दोषी ठहराया गया और प्रत्येक को दस साल के लिए कठोर कारावास और 1,00,000/- जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई। जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

2. अपीलकर्ता राजू प्रेमजी (ए-4) शिलांग के निवासी थे। हालाँकि, वह पश्चिम बंगाल में जूतों का कारोबार कर रहा था एवं अपीलकर्ता अरुण कानूनगो (ए-3) मेघालय के निवासी हैं। उन पर दो अन्य आरोपियों, यशिहे योबिन (ए-1) और लिशिहे न्गवाज़ा न्गवाज़ा (ए-2) के साथ एनडीपीएस अधिनियम के तहत अपराध करने के लिए मुकदमा चलाया गया था।

3. मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स को रिकॉर्ड पर रखने से पहले, जी हम देख सकते हैं कि आरोपी नंबर 1 और 2 को 380 ग्राम हेरोइन रखने के लिए दोषी ठहराया गया है। यहां अपीलकर्ताओं को हेरोइन के लिए दुष्प्रेरण के लिए अधिनियम की धारा 25 के तहत दोषी ठहराया गया था क्योंकि उनका कथित तौर पर हेरोइन के निपटान में संभावित खरीदारों को खोजने में खुद को शामिल करना था।

4. अभियोजन पक्ष का मामला संक्षेप में यह है कि डी. पाकिनटेन, पीडब्लू-11, सीमा शुल्क आयुक्त के कार्यालय में एक निरीक्षक जिन्हें एनईआर शिलांग को मेघालय पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन टीम से एन.के. भण्डारी पीडब्लू-4, के माध्यम से एक सूचना शाम लगभग 7.50 बजे 19 अगस्त, 2003 को प्राप्त हुई दम दम, नोगथिम्मई के एक यासिहे योबिन, आरोपी नंबर 1, ने अपने आवास पर कुछ हेरोइन रखी थी और अगर तुरंत तलाशी ली जाए, तो प्रतिबंधित पदार्थ बरामद किया जा सकता है। इसके बाद पाकिनटेन ने आर.एम. से संपर्क किया। चीने, अधीक्षक (पीडब्लू-7), बी. कार, निरीक्षक (पीडब्लू-2) और एन.के. भंडारी, पीडब्लू-4। वे सभी तलाशी लेने के लिए आरोपी नंबर 1 के आवास की ओर बढ़े। वहां पहुंचकर उनकी मुलाकात योबिन समेत स्पेशल ऑपरेशन टीम के सदस्यों से हुई. योबिन का विवरण सुनिश्चित होने के बाद, स्वतंत्र गवाहों आर.वी. की उपस्थिति में उसके घर की तलाशी ली गई। डीखा, पीडब्लू-3 और डी. खिरीम, पीडब्लू-8, इस दौरान उसने एक सूटकेस निकाला जिसमें उसने

कथित तौर पर हेरोइन का पैकेट रखा था। हालाँकि, वहाँ कोई हेरोइन नहीं मिली। मौके पर पूछताछ करने पर योबिन ने बताया कि उसके बहनोई लिसिहे न्गवाज़ा, आरोपी नंबर 2, ने इसे हटा दिया होगा। उसने अपनी पत्नी को निर्देश दिया कि वह उससे संपर्क करे और सामान लेकर तुरंत वापस आने को कहे। आरोपी नंबर 2 कुछ देर बाद अपने कंधे पर काला बैग लेकर आया। पूछने पर उसने बैग खोला और उसमें से सामान निकाला जिसमें सिंथेटिक कपड़े से बने कैमोफ्लेज डेनिम का एक सूटकेस कवर और एक हरा पॉलिथीन बैग था, जिसे खोलने पर एक प्लास्टिक पैकेट जिसमें सफेद पाउडर लिपटा हुआ था, जिसमें अंग्रेजी अखबार के दो टुकड़े थे। बरामद किया गया.

5. हालांकि, निर्विवाद रूप से, सूचना पीडब्लू-9 एम. खारकांग, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, को उनके स्रोत से प्राप्त हुई थी, जिन्होंने बताया था कि उन्हें कुछ लोगों द्वारा ड्रग्स बेचने की पेशकश की गई थी और उन्हें कीटिंग रोड पर उनसे मिलना होगा। जिस पर सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी तैनात किए गए, जिन्होंने अपीलकर्ताओं को वहां से पकड़ लिया। उन्हें पुलिस अधीक्षक कार्यालय लाया गया। अपीलकर्ताओं की भौतिक खोज की गई लेकिन कुछ भी नहीं मिला। उनसे पूछताछ की गई, जिसमें उन्होंने उसी समय सीमा शुल्क अधिकारियों को सूचित किया गया। पुलिस अधिकारी जहां पहले आरोपी नंबर 1 के गांव पहुंचे, वहीं कस्टम अधिकारी बाद में उनके साथ पहुंचे.

6. यहां अपीलकर्ता पुलिस की हिरासत में थे अधिकारी 19 अगस्त, 2003 की शाम से उनकी हिरासत में थे को सीमा शुल्क अधिकारियों को सौंप दिया गया। अब रिकॉर्ड से पता चला है कि सभी आरोपियों ने 20 अगस्त, 2003 को अधिनियम की धारा 67 के तहत दो-दो बयान दिए थे। जहां तक आरोपी नंबर 4 का सवाल है, उसके द्वारा दिए गए बयानों को एक्सटेंशन 17 और 18 के रूप में चिह्नित किया गया था, जबकि आरोपी नंबर 3 के बयानों को एक्सटेंशन के रूप में चिह्नित किया गया था। 13 और 14. एक औपचारिक प्रथम 20 की दोपहर में ही सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी अगस्त, 2003. सभी आरोपी व्यक्तियों को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया शाम 4.30 बजे उनसे आगे की पूछताछ की गई और दोनों अपीलकर्ताओं ने 21 अगस्त, 2003 को तीसरा बयान दिया जिन्हें Exts के रूप में चिह्नित किया गया था। क्रमशः 19 और 15. उसी दिन मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। जबकि आरोपी नंबर 4 नवंबर 2003 को अपने कबूलनामे से मुकर गया, आरोपी नंबर 3 सहित अन्य आरोपी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अपने बयान देते समय उससे पीछे हट गए।

7. 21 नवंबर, 2003 को अधिनियम की धारा 21, 28 और 29 के तहत अपराध करने के लिए अपीलकर्ताओं के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था। जैसा कि ऊपर कहा गया है, उन्हें दोषी ठहराया गया था।

उच्च न्यायालय के समक्ष उनके द्वारा की गई अपील पर विचार किया गया है। आक्षेपित निर्णय के कारण खारिज कर दिया गया।

आरोपी नंबर 1 और 2 ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ इस न्यायालय के समक्ष कोई अपील नहीं की है।

8. श्री यू.यू. ललित, वरिष्ठ वकील और श्री विकास महाजन, वकील, इन अपीलों के समर्थन में निम्नलिखित तर्क उठाएंगे: -

क. अपीलकर्ताओं द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों के समक्ष दिए गए कथित बयान हिरासत में दिये गये थे, वह साक्ष्य अधिनियम, 1872. की धारा 26 के तहत बाधित होते है।

ख. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अभियुक्तों को कोई बयान देने के लिए नहीं बुलाया गया था और ऐसे बयान तब दिए गए थे जब वे हिरासत में थे, ये साक्ष्य में पूरी तरह से अस्वीकार्य थे।

ग. किसी भी घटना में, अपीलकर्ता अपने पहले के बयानों से मुकर गए हैं, भौतिक विवरण में किसी भी पुष्टि के अभाव में उस पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है।

घ. भले ही अभियुक्तों द्वारा दिए गए बयानों को ध्यान में रखा जाए, उन्होंने कथित तौर पर किसी भैया जी को उल्लंघन की बिक्री की पेशकश की थी.. जिन पर मुकदमा नहीं चलाया गया था, हालांकि बुलाया गया था, लगाए गए निर्णयों को रद्द किया जा सकता है।

9. दूसरी ओर, उत्तरदाता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील सुश्री श्रबानी चक्रवर्ती ने आग्रह किया:-

क. अपीलकर्ताओं ने सीमा शुल्क अधिकारियों के अधिकारियों के समक्ष बयान दिया है जो अधिनियम की धारा 67 के संदर्भ में पुलिस अधिकारी नहीं थे, साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 26 में निहित बयान की अस्वीकार्यता के संबंध में बार लागू नहीं होगा।

ख. अपीलकर्ताओं के बयानों की पुष्टि अन्य आरोपी व्यक्तियों के बयानों से की गई है, आक्षेपित निर्णय अप्राप्य है।

ग. आरोपी नंबर 1 और 2 के पास प्रतिबंधित पदार्थ पाया गया है और अपीलकर्ताओं को अपराध के लिए उकसाने का दोषी पाया गया है, इसलिए यह उनके लिए है कि वे इसके संबंध में उचित स्पष्टीकरण दें।

10. एनडीपीएस अधिनियम का अध्याय III निषेध, नियंत्रण और विनियमन का प्रावधान करता है। अध्याय IV अपराध और दंड का प्रावधान करता है।

अधिनियम की धारा 8 अन्य बातों के साथ-साथ उसमें उल्लिखित उद्देश्यों को छोड़कर, कुछ कार्यों पर रोक लगाती है। धारा 21 निर्मित दवाओं और तैयारियों के संबंध में उल्लंघन के लिए सजा का प्रावधान करती है। धारा 28 अपराध करने के प्रयास के लिए सजा का प्रावधान करती है। धारा 29 में उकसाने और आपराधिक साजिश के लिए बी सजा का प्रावधान है।

11. अधिनियम में कड़ी सजा का प्रावधान है। जहां कोई क़ानून कठोर शक्ति प्रदान करता है और जमानत देने से संबंधित मामले सहित कठोर दंडात्मक प्रावधानों का प्रावधान करता है, वहां पूर्ववर्ती शर्तों का ईमानदारी से पालन किया जाना चाहिए।

पुलिस अधिकारियों को एक सूचना मिली. पुलिस अधिकारी एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के तहत सशक्त अधिकारी थे। उन्हें इसे लिखित में देना था ताकि उच्च अधिकारियों को इसके बारे में अवगत कराया जा सके। कोई तलाशी वारंट या प्राधिकरण प्राप्त नहीं किया गया था। कुछ सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी तैनात किये गये। उन्हीं के शब्दों में अभियोजन पक्ष के गवाहों और विशेष रूप से गवाह पीडब्लू 9 और 10, एम. खरक्रांग, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एस.आई. एन. थापा, क्रमशः अपीलकर्ताओं को पकड़ लिया गया। छापेमारी अन्य बातों के साथ-साथ एस.आई. एन. थापा, पीडब्लू-10 द्वारा की गई। उन्हें हिरासत में लिया गया और पीडब्लू-9 के कार्यालय में लाया गया। फिर भी उनसे कोई बयान देने के लिए नहीं कहा गया. उन्हें बुलाया तक नहीं गया. अधिनियम की धारा 50 के प्रावधानों का अनुपालन किए बिना उनके व्यक्तियों की तलाशी ली गई। जाहिर तौर पर उनसे पूछताछ की गई. पूछताछ में ही उन्होंने आरोपी नंबर 1 के एफ पते के बारे में खुलासा किया। उपरोक्त स्थिति में, यह समझना मुश्किल है कि सीमा शुल्क अधिकारियों को क्यों सूचित करना पड़ा। पुलिस अधिकारी स्वयं तलाशी और जब्ती कर सकते थे। इसके लिए

सशक्त होने के कारण उन्हें अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना चाहिए था। हम मान सकते हैं कि सीमा शुल्क अधिकारियों को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 53 के तहत जारी अधिसूचना के संदर्भ में एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी की शक्तियां प्रदान की गई थीं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पुलिस अधिकारियों को उनके अधिकार क्षेत्र से वंचित कर दिया गया था।

12. पुलिस अधिकारियों को मामला सीमाशुल्क अधिकारियों को स्थानांतरण क्यों करना चाहिए था किसी भी तर्क को खारिज करता है। यह स्वीकार किया गया है कि अपीलकर्ताओं को पीडब्लू, 9 और 10 सहित पुलिस अधिकारियों द्वारा ग्राम नोंगघिमई में ले जाया गया था, जहां का आरोपी नंबर 1 निवासी था। सीमा शुल्क अधिकारी बहुत बाद में उनके साथ शामिल हुए। आरोपी नंबर 1 के घर की तलाशी विशेष रूप से सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा नहीं की गई थी। मौजूद सभी पुलिस अधिकारी खोजबीन में जुट गये. जाहिर तौर पर तलाश सूर्यास्त के बाद की गई। जैसा कि पीडब्लू-9 को शाम लगभग 6.30 बजे सूचना प्राप्त हुई; जैसा कि अदालत के समक्ष उसके बयान से स्पष्ट है कि वह रात लगभग 10.00 बजे आरोपी नंबर 1 के घर से निकला था। जबकि सीमा शुल्क अधिकारी अभी भी कुछ अन्य औपचारिकताएँ निभा रहे थे। चारों आरोपियों को आगे की पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन लाया गया और अगली तारीख पर सीमा शुल्क अधिकारियों ने पुलिस अधिकारियों को सूचित किया कि उन दोनों

को गिरफ्तार करना आवश्यक है। उस समय ही उनकी अभिरक्षा सीमा शुल्क अधिकारियों को सौंप दी गई थी।

13. पीडब्लू-7, आर.एम. चाइन, निर्विवाद रूप से वह अधिकारी था जिसके सामने कथित बयान दिए गए थे। यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि उन्हें कोई समन भेजा गया था। ऐसा कोई सम्मन रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया था।

14. यह मान लिया गया था कि कोई डील नहीं हुई थी. अभियुक्तगण एवं सूचक आपस में ही बात कर रहे थे। वह उनकी बातचीत भी नहीं सुन सका। स्वीकृत रूप से मुखबिर एक भैया जी ही थे। उनकी जांच नहीं की गई जिसके लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

15. माना कि प्रत्येक आरोपी से तीन बयान लिए गए। पहला एक कथात्मक था। दूसरा सवाल-जवाब के रूप में था. औपचारिक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के बाद तीसरा बयान स्वीकारोक्तिपूर्वक लिया गया।

16. यह माना जाता है कि संबंधित अधिकारी, आर.एम. चाइन, पीडब्लू-7, ने सोचा कि अभियुक्तों से बिना संख्या के कई बार पूछताछ की जा सकती है जब तक कि वे अपनी संतुष्टि के अनुरूप उत्तर नहीं देते।

17. धारा 67 के प्रावधानों का लागू होना

उपरोक्त तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में एक अधिनियम पर विचार करना आवश्यक है। यह इस प्रकार है-

धारा 67 -सूचना आदि मांगने की शक्ति।

धारा 42 में निर्दिष्ट कोई भी अधिकारी जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अधिकृत है, इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के संबंध में किसी भी जांच के दौरान, -

(ए) खुद को संतुष्ट करने के उद्देश्य से किसी भी व्यक्ति से जानकारी मांग सकता है कि क्या इस अधिनियम या इसके तहत बनाए गए किसी नियम या आदेश के प्रावधानों का कोई उल्लंघन हुआ है;

(बी) किसी भी व्यक्ति से कोई दस्तावेज़ तैयार करने या वितरित करने की अपेक्षा करना

या पूछताछ के लिए उपयोगी या प्रासंगिक चीज़;

(सी) तथ्यों और मामले की परिस्थितियाँ से परिचित किसी भी व्यक्ति की जांच करें ।

18. इसलिए, एक सशक्त अधिकारी, अधिनियम के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के संबंध में किसी भी जांच के दौरान, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित किसी भी व्यक्ति से पूछताछ करने का हकदार है। चूंकि 'पूछताछ' शब्द को एनडीपीएस अधिनियम के तहत परिभाषित नहीं किया गया है, इसका अर्थ आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 2 (जी) के साथ-साथ व्युत्पत्ति संबंधी अर्थ में भी दिया गया है और जिस तरीके से एफ को लागू किया जा सकता है।

19. प्रारंभ से ही यह स्वीकार किया गया कि अपीलकर्ता पुलिस हिरासत में थे। उनसे पुलिस अधिकारियों ने पूछताछ की। वे स्वतंत्र व्यक्ति नहीं थे. वे संयम के आदेशों के अधीन थे और इस प्रकार पुलिस अधिकारियों की हिरासत में होंगे। किसी पुलिस अधिकारी की हिरासत में रहते हुए उनके द्वारा दिया गया कोई भी बयान भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 26 के संदर्भ में साक्ष्य के रूप में अस्वीकार्य होगा, जो इस प्रकार है:-

"26. पुलिस की हिरासत में रहते हुए अभियुक्त द्वारा कबूल किया गया बयान उसके खिलाफ साबित नहीं किया जाएगा - किसी के द्वारा किया गया कोई बयान सिद्ध नहीं व्यक्ति जब किसी पुलिस अधिकारी की हिरासत में हो, जब तक कि यह किसी मजिस्ट्रेट की तत्काल उपस्थिति में न किया गया हो,ऐसे व्यक्ति के खिलाफ साबित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण -इस खंड में "मजिस्ट्रेट" में फोर्ट सेंट जॉर्ज या अन्यत्र प्रेसीडेंसी में मजिस्ट्रेट कार्यों का निर्वहन करने वाले गांव के मुखिया को शामिल नहीं किया गया है, जब तक कि ऐसा मुखिया दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 के तहत मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने वाला मजिस्ट्रेट न हो। (1898 का वी)।"

20. सीमा शुल्क अधिकारी द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार। केंद्र सरकार पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी था। इसलिए, एक पुलिस

स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को उपलब्ध सभी शक्तियाँ उसके पास उपलब्ध थीं। एक प्रभारी अधिकारी की शक्ति का एक गुण संज्ञेय अपराध के आयोग की जांच करने की शक्ति है। वह आरोप पत्र भी दाखिल कर सकते हैं.

21. पंजाब राज्य बनाम बलदेव सिंह, [(1999) 6 एससीसी 172] में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने निम्नानुसार निर्णय दिया: -

"28. यह न्यायालय उस संदर्भ को नजरअंदाज नहीं कर सकता जिसमें एनडीपीएस अधिनियम लागू होता है और विशेष रूप से नशीली दवाओं के अपराधों के लिए जांच के अधीन व्यक्तियों के बीच व्यापक निरक्षरता का कारक है। यह ध्यान में रखना चाहिए कि सजा जितनी गंभीर होगी, उतनी ही अधिक देखभाल की जानी होगी देखें कि कानून में दिए गए सभी सुरक्षा उपायों का ईमानदारी से पालन किया जाता है। हम इस बात का कोई कारण नहीं ढूंढ पा रहे हैं कि अधिकार प्राप्त अधिकारी को संदिग्ध को वास्तविक अवसर देने से क्यों बचना चाहिए, उसे यह बताकर कि उसे यह अधिकार है कि "यदि उसे "किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में तलाशी लेने की आवश्यकता है, उसकी तलाशी केवल उसी तरीके से की जाएगी। जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है कि धारा 50 में निहित प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों के अनुपालन का उद्देश्य दोहरे उद्देश्य की पूर्ति करना है - एक की रक्षा करना।" झूठे आरोपों और

तुच्छ आरोपों के खिलाफ व्यक्ति के साथ-साथ अधिकार प्राप्त अधिकारी द्वारा की गई तलाशी और जब्ती को विश्वसनीयता प्रदान करना।

यह तर्क कि बढ़ती नशीली दवाओं के खतरे को ध्यान में रखते हुए, धारा 50 में निहित सभी सुरक्षा उपायों के अनुपालन पर जोर देने से अधिक बरी हो सकते हैं, हमें पसंद नहीं आता। यदि अधिकार प्राप्त अधिकारी धारा 50 की आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहता है और उस आधार पर कोई आदेश या बरी दर्ज किया जाता है, तो अभियोजन पक्ष को अपनी गलतियों के लिए खुद को धन्यवाद देना चाहिए। वास्तव में हर मामले में अंतिम परिणाम महत्वपूर्ण है लेकिन इसे प्राप्त करने के साधन बोर्ड से ऊपर रहने चाहिए। इलाज बीमारी से बदतर नहीं हो सकता. यदि अदालत को तलाशी अभियान के दौरान जांच एजेंसी द्वारा किए गए अराजकता के कृत्यों को नज़रअंदाज करते देखा जाता है, तो न्यायिक प्रक्रिया की वैधता संदेह के घेरे में आ सकती है और यह कानून के प्रति सम्मान को भी कम कर सकती है और न्याय प्रशासन के साथ अनजाने में समझौता करने का प्रभाव हो सकता है। इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती।"

22. इस उद्देश्य के लिए, हम मान लेंगे कि इस तरह की स्वीकारोक्ति साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 25 के अंतर्गत नहीं आती है, लेकिन फिर भी उन्हें कड़ी जांच करनी चाहिए।

इस न्यायालय ने कन्हैयालाल बनाम भारत संघ, [(2008) 4 एससीसी ई 668] में, निर्णयों की संख्या पर विचार करते हुए, निम्नानुसार निर्णय लिया: -

> "43. इस अपील पर निर्णय लेने में शामिल कानून पर इस न्यायालय द्वारा 1963 में प्यारे लाल भार्गव मामले में विचार किया गया है। एनडीपीएस अधिनियम की धारा 67 के प्रावधानों के तहत किए गए कबूलनामे के संबंध में सुसंगत दृष्टिकोण अपनाया गया है। और सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 जैसे अन्य आपराधिक अधिनियमों में कहा गया है कि ऐसे बयानों को साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के प्रयोजन के लिए स्वीकारोक्ति के रूप में माना जा सकता है, लेकिन सावधानी के साथ कि अदालत को खुद को संतुष्ट करना चाहिए कि ऐसे बयान दिए गए थे स्वेच्छा से और ऐसे समय में जब ऐसा बयान देने वाले व्यक्ति को कथित अपराध के संबंध में आरोपी नहीं बनाया गया था।"
>
> 23. क्या इकबालिया बयान स्वैच्छिक और मुफ़्त है

सीमा शुल्क एनईआर शिलांग इकाई आई.एस.बी. सिन्हा, जे.] किसी भी दबाव का निर्णय प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से किया जाना चाहिए।

यह कोर्ट मोहतेशाम मो. इस्माइल बनाम विशेष. निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय, [(2007) 8 एससीसी 254], के रूप में आयोजित किया गया है

अंतर्गत:-

20. हालाँकि, हम देख सकते हैं कि हाल ही में फ्रांसिस स्टेनली बनाम इंटेलिजेंस ऑफिसर, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, तिरुवनंतपुरम में इस न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया है कि स्वीकारोक्ति केवल तभी स्वीकार की जा सकती है जब वह स्वैच्छिक और दबाव से मुक्त पाई जाए। किसी प्राधिकारी के समक्ष कथित तौर पर की गई स्वीकारोक्ति की बारीकी से जांच की आवश्यकता होगी। इसके अलावा अब यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि अदालत को स्वतंत्र स्रोतों से कथित स्वीकारोक्ति की पुष्टि की मांग करनी चाहिए।"

नूर आगा बनाम पंजाब राज्य और अन्य में। [2008 (9)

स्केल 681], इस न्यायालय ने कहा:-

"102. क्वीन एम्प्रेस बनाम बाबूलाल [आईएलआर (1884) 6 ऑल. 509] मामले में महमूद जे. के शब्दों में साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 अधिनियमित की गई थी, ताकि पुलिस अधिकारियों से अपराध स्वीकारोक्ति की जबरन वसूली पर रोक लगाई जा सके। आरोपी व्यक्तियों के मुकदमे के दौरान इस तरह की जबरन वसूली प्रदान करने के लाभ के रूप में।

इसलिए, इसे एक उच्च उद्देश्य की पूर्ति के लिए अधिनियमित किया गया था।"

24. किसी भी स्थिति में यदि वे पुलिस अधिकारियों और सीमा शुल्क अधिकारियों की हिरासत में थे, हालांकि वे शब्द के सख्त अर्थ में आरोपी नहीं थे, उनके द्वारा किया गया कोई भी बयान साक्ष्य अधिनियम की धारा 26 के संदर्भ में स्वीकार्य नहीं होगा।, 1872.

25. झुके हुए वकील ने कोचन वेलायुधन बनाम केरल राज्य, [एआईआर 1961 केरल 8] में केरल उच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है, जिसमें यह देखा गया था: -

"21. रामराव एकोबा बनाम द क्राउन, एआईआर 1951 नाग 237 हेमोन, जे. ने कहा कि:

"हालांकि खोजों को विनियमित करने वाले प्रावधानों का पालन करने में विफलता खोज करने वाले अधिकारियों की विश्वसनीयता पर संदेह पैदा कर सकती है, लेकिन कानून में ऐसा कुछ भी नहीं है जो अनियमित खोज से संबंधित साक्ष्य को अस्वीकार्य बनाता है और ऐसे साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि अमान्य नहीं है अकेले उस ज़मीन पर"

26. कुछ दिनों के बाद ही आरोपी नंबर 4 द्वारा कबूलनामा वापस ले लिया गया। विद्वान विशेष न्यायाधीश ने इस तरह की वापसी के तथ्य पर विचार किया है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते

हुए, हमारी दृढ़ राय है कि स्वीकारोक्ति को अपीलकर्ताओं द्वारा स्वेच्छा से किया गया नहीं कहा जा सकता है।

चूंकि अपीलकर्ताओं के पास प्रतिबंधित पदार्थ नहीं पाया गया, इसलिए साबित करने का बोझ उन पर कभी नहीं पड़ा।

27. उपरोक्त कारणों से ये अपीलें स्वीकार की जाती हैं। यदि अपीलकर्ताओं को तत्काल रिहा करने का निर्देश दिया जाता है

किसी अन्य मामले के संबंध में इसकी आवश्यकता नहीं है।

अपील की अनुमति.

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी दीपक पांडे (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।